भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1086

07.02.2020 को उत्तर के लिए

मंडकोल आरक्षित वन

1086. श्री राजमोहन उन्नीथन :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल और कर्नाटक राज्यों के बीच मंडकोल आरक्षित वन की अंतर-राज्यीय सीमा को बस्ती और भू अभिलेख सर्वेक्षण आयोग, बंगलुरु की सिफारिश पर ट्रेवर्स शीट्स के आधार पर अंतिम रूप देने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) कर्नाटक सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार कर्नाटक और केरल राज्यों के बीच अवस्थित मंडकोल आरक्षित वन की अंतर-राज्यीय सीमा के सर्वेक्षण को अंतिम रूप देने के संबंध में बस्ती और भू-अभिलेख सर्वेक्षण आयोग मौजूद है। तथापि, केरल और कर्नाटक राज्यों के बीच मंडकोल आरक्षित वन की अंतर-राज्यीय सीमा को ट्रेवर्स शीट्स के आधार पर अंतिम रूप देने के लिए बस्ती और भू अभिलेख सर्वेक्षण आयोग, बंगलुरू द्वारा की गई सिफारिश के संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ है।

कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि उपायुक्त, मंगलुरू द्वारा दिनांक 15.11.2010 को एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें उपनिदेशक भू-अभिलेख (डीडीएलआर), दक्षिण कन्नड जिला तथा उप-निदेशक सर्वेक्षण और भू-अभिलेख (डीडीएसएलआर), कासरगोड को दल प्रमुख के रूप में शामिल करके कर्नाटक-केरल अंतर-राज्यीय सीमा का संयुक्त रूप से सत्यापन करने का निर्णय लिया गया था। केरल सरकार ने अनुरोध किया है कि मंडकोल आरक्षित वन का मूल स्केच प्राप्त कर लेने के बाद ही सर्वेक्षण आरंभ कराया जाए।

****